6. बिजली की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में, 11.2 मेगावाट के 4 डी. जी. सेटों को चालू कर दिया गया है।

7. एक बाहरी परामर्शदाता के मार्ग-दर्शन में निष्पादन योजना में कुल सुधार करने को अन्तिम रूप दिया गया है और यह कार्यान्वयनाधीन है।

8. एक बाहरी परामर्शदाता मैसर्स लवलुक एण्ड लुइस की सहायता से संगठनात्मक ढांचे का बृहद युक्तिकरण कार्य पूरा कर लिया गया है।

9. वर्ष 1993–94 के लिए 16.50 करोड़ रुपये की लागत कटौती योजना बना ली गई है जिसका सक्रिय रूप से पालन किया जा रहा है। योजना का मुख्य बल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के माध्यम से श्रमशक्ति को घटाने, बेशी श्रमशक्ति तथा उपलब्ध कि-फायती सामग्री का उपयोग करने, धातुमिश्रण सामग्री की खपत में कमी करने और इंजीनियरिंग आदि को प्रभावोत्पादक बनाने पर है। अप्रैल 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि में लागत में 9.28 करोड़ रुपये की कटौती कर ली गई है।

10. संगठन के सभी स्तरों पर संचार माध्यम को मजबूत बना दिया गया है।

11. अनुशासन तथा समय की पाबंदी में सुधार किया गया है।

12. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. में बेशी श्रमशक्ति के युक्तिकरण के लिए कंपनी में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्कीम लागू है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत दिनांक 1.2.1994 तक सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या 4105 है। कंपनी द्वारा चालू वर्ष में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत और अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि चालू वर्ष के अंत तक लगभग 13,000 कर्मचारी रह जाएं।

13. कंपनी ने एक टर्न अराउंड योजना तैयार की है जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को संदर्भित किया गया है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कहा था कि वह कंपनी की टर्न अराउंड योजना की जांच करें और अपनी सिफारिशें फरवरी, 1994 के अंत तक प्रस्तुत कर दें। टर्न अराउंड योजना की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जांच की जा रही है और उनकी सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

14. जैसे ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सिफारिशें मिल जाती हैं और सभी संबंधित एजेंसियों तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनरूद्धार योजना स्वीकार कर ली जाती है, वैसे ही इसको कार्यान्वित किया जाएगा और कंपनी के पुनरूद्धार हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Investment proposals received from German investors

5915. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any investment proposals particularly those in infrastructure sector in response to Prime Minister's invitation to German investors, made during his recent visit to that country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) During his official visit to Germany from February 2-5, 1994, Prime Minister met representatives of German Business and Industry with a view to invite them to look at India as a trade and investment partner and generate increased interest among potential investors. Receipt and consideration of proposals from German investors is a continuing process. Approvals have already been accorded to 205 proposals for foreign direct investment by German firms in Indian companies in the post policy period i.e. from Aogust, 1991 to March, 1994 involving froeign investment of Rs. 339.09 crores. 15 proposals of foreign direct investment approved during February-March, 1994 envisaging investment by German companies is of the order of Rs. 52.2 crores in sectors such as metallurgical industry, industrial machinery, prime movers, polymer based products, homoepathic and herbal medicines, leather wallets, air brake systems for railway vehicles, computer software, electric power tools and trading.

Indian Leather Industry

5916. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian leather industry has the advantage of good quality raw materail, cheap labour and skilled craftsmen;

(b) whether it is also a fact that inspite of these advantages there is delay in delivery of orders, lack of proper quantity control, inadequate investment in latest technology; and

(c) if so, the steps being taken to remove these handicaps and boost the industry;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) These drawbacks do not hold good for the entire industry.

(c) The Government launched in the year 1992, a Programme—National Leather Development Programme—with a view to strengthen the institutional support for the industry in the areas of Human Resources Development, Design & Product Development, Testing & Quality Control, enhanced export capability, Developing Supporting infrastructure and Systems of Coordination.

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ भारत में निवेश के संबंध में बातचीत

5917. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के बीच ब्रिटेन द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने के संबंध में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बातचीत के परिणामस्वरूप स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत में ब्रिटेन से और अधिक पूंजी निवेश आकृष्ट करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत में ज्यादा निवेश पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को आमंत्रित किया गया था। ब्रिटिश प्रधान मंत्री को सूचित किया कि वह भारतीय व्यापार तथा निवेश बाजार की मुक्तता के बारे में ब्रिटिश व्यापारियों को बतायेंगे और ब्रिटेन द्वारा अधिक पूंजी निवेश करने को कहेंगे।